(Rupees in Crores)

Plant	1997-98
Bhilai Steel Plant	701
Durgapur Steel Plant	(−)509
Rourkela Steel Plant	(−)374
Bokaro Steel Plant	367
Alloy Steels Plant	(−)88
Salem Steel Plant	(−)120
Raw Materials Division & Central Unit	171

(d) SAIL has taken number of steps to improve the performance, which inter-alia include reduction in cost by improving the quality of products, and increasing sales through aggressive and customer oriented marketing, etc.

देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिये परिव्यय

3621. **श्री अखिलेश दासः** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नौवीं योजना के दौरान देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिये कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है;

(ख) उक्त योजना के दौरान कितने नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उपरोक्त परिव्यय में राज्य सरकारों के लिये कितने प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है; और

(घ) उपरोक्त योजना के दौरान इस्पात उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) योजना आयोग के तत्वाधान में लोहा और इस्पात क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु एक कार्यदल गठित किया गया था। कार्यदल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लोहा और इस्पात क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र (19,681.00 करोड़ रुपये) और निजी क्षेत्र (32,493.00 करोड़ रुपए) दोनों क्षेत्रों के लिए कुल 52,174 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया है। योजना आयोग ने इस्पात क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सही-सही निवेश निर्धारित करने के लिए विस्तृत और गहन विचार-विमर्श किया है। इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने अंतिम रूप से 19,197.88 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया है। कार्यदल द्वारा पहले लगाए गए अनुमान के अनुसार निजी क्षेत्र का निवेश वही रहेगा। अब इस्पात क्षेत्र (सरकारी और निजी दोनों) में कुल 51,690.88 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। लोहा और इस्पात क्षेत्र के लिए अलग से राज्य-वार कोई आवंटन नहीं है।

अब सरकार का सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार नहीं है। नई औद्योगिक नीति की शुरूआत से ही लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश में लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थान स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। चूंकि इस्पात उद्योग को बाजार के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है, इसलिए इस्पात संयंत्र स्थापित करने आदि के लिए निवेश से संबंधित निर्णय लेना उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय का मामला है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2001-02) तक परिसज्जित इस्पात की अनुमानित घरेलू उपलब्धता लगभग 380 लाख टन है। बहरहाल, योजना आयोग द्वारा परिसज्जित इस्पात के उत्पादन और इस्पात क्षेत्र में निवेश संबंधी लक्ष्यों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Implementation of Capital Restructuring programme in Nalco

3622. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the National Aluminium Company has implemented its capital restructuring programme;

(b) if so, the details of the programme;

(c) the reaction of the Government thereto; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) No Sir, National Aluminium Company Limited (NALCO) has submitted its proposal for capital restructuring to the Government.

(b) to (d) Does not arise.